

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *20
TO BE ANSWERED ON 05.02.2024

PROMOTION OF MSMEs IN ODISHA

*20. SHRI SUJEET KUMAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the details of the steps taken by Government to promote MSMEs in the State of Odisha, under Atmanirbhar Bharat Abhiyan (ABA);
- (b) whether any scheme is being implemented by Government to promote small scale industries in tribal areas of Odisha;
- (c) if so, the details thereof including the due date for its implementation; and
- (d) the number of places where small scale industry project centres are running in the State of Odisha, district-wise details thereof?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI NARAYAN RANE)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *20 FOR ANSWER ON 05.02.2024.

(a) to (c): The Government has taken a number of recent steps to promote Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), in the country including tribal areas of Odisha under Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. These include:

- New revised criteria for defining MSMEs.
- “Udyam Registration” for MSMEs, for Ease of Doing Business w.e.f. 1.7.2020.
- Rs. 50,000 crore equity infusion through Self Reliant India Fund.
- Rs. 5 lakh crore Emergency Credit Line Guarantee Scheme, for businesses, including MSMEs. The scheme was operational till 31.03.2023
- No global tenders for procurement up to Rs. 200 crores.
- Launching of an online Portal “Champions” in June, 2020 to cover many aspects of e-governance including grievance redress and handholding of MSMEs.
- Inclusion of Retail and Wholesale traders as MSMEs w.e.f. 2.7.2021.
- Non-tax benefits extended for 3 years in case of an upward change in status of MSMEs.
- Launch of Udyam Assist platform (UAP) on 11.01.2023 to bring Informal Micro Enterprises (IMEs) under the formal ambit for availing the benefit under Priority Sector Landing.

The Ministry of MSME implements various schemes/ programmes for the promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector across the country, including in the tribal areas of Odisha State which inter alia include Raising and Accelerating Performance (RAMP), PM Vishwakarma Scheme, Entrepreneurship Skill Development Programme (ESDP), Procurement and Marketing Support Scheme (PMSS), Micro and Small Enterprises-Cluster Development Programme (MSE-CDP), MSME Champions Scheme and Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises.

(d): Additionally, to promote the small scale industry in the country including the State of Odisha, Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) extends Margin Money support to Micro Enterprises. The district-wise details of micro units set up, margin money disbursed and employment generated under PMEGP in the State of Odisha, are given at *Annexure-I*.

Annexure referred to part (d) of the Rajya Sabha Starred Question No. *20 for answer on 05.02.2024.

Detail for project assisted under Prime Minister's Employment Generation Programme during current Financial Year-2023-24 in the State of Odisha (District –wise) (Project & Employment: in numbers, Margin Money: Rs. In lakhs)				
Sr. No.	State/ District	2023-24 (as on 30.01.2024)		
		No. of Projects	M.M (Rs. In lakhs)	Employment
1	Angul	71	286.89	568
2	Baleswar	133	465.34	1,064
3	Bargarh	82	250.15	656
4	Bhadrak	86	260.08	688
5	Balangir	82	252.96	656
6	Boudh	10	23.59	80
7	Cuttack	165	513.99	1320
8	Deogarh	29	67.05	232
9	Dhenkanal	73	279.43	584
10	Gajapati	18	45.28	144
11	Ganjam	170	681.72	1360
12	Jagatsinghpur	54	151.85	432
13	Jajpur	80	211.80	640
14	Jharsuguda	37	93.45	296
15	Kalahandi	51	147.79	408
16	Kandhamal	16	31.58	128
17	Kendrapara	101	297.29	808
18	Keonjhar	54	158.62	432
19	Khurdha	203	688.77	1624
20	Koraput	30	97.48	240
21	Malkangiri	24	51.04	192
22	Mayurbhanj	134	416.34	1072
23	Nabarangpur	26	45.47	208
24	Nayagarh	75	220.40	600
25	Nuapada	15	46.00	120
26	Puri	176	554.92	1408
27	Rayagada	49	154.46	392
28	Sambalpur	31	95.15	248
29	Sonepur	54	174.36	432
30	Sundargarh	59	172.73	472
	Total	2,188	6,935.98	17,504

Source: Khadi and Village Industries Commission (KVIC)

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *20
उत्तर देने की तारीख : 05.02.2024

ओडिशा में एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाना

*20. श्री सुजीत कुमार :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) आत्मनिर्भर भारत अभियान (एबीए) के तहत ओडिशा राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना लागू की जा रही है;
- (ग) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की नियत तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) ओडिशा राज्य में कितने स्थानों पर लघु उद्योग परियोजना केंद्र चल रहे हैं, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नारायण राणे)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *20, जिसका उत्तर दिनांक 05.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए नए संशोधित मानदंड।
- व्यापार की सुगमता हेतु दिनांक 01.07.2020 से एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण"।
- आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
- एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। यह योजना 31.03.2023 तक चल रही थी।
- 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
- शिकायत निवारण और एमएसएमई को हैंडहोल्डिंग सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ।
- दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना।
- एमएसएमई के स्तरोन्नयन के मामले में 3 साल के लिए गैर-कर लाभ प्रदान करना।
- प्राथमिकता क्षेत्र लेंडिंग के तहत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

एमएसएमई मंत्रालय पूरे देश में जिसमें ओडिशा राज्य के आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन (आरएएमपी), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), प्रापण और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई चैंपियंस योजना और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शामिल हैं।

(घ) : इसके अतिरिक्त, ओडिशा राज्य सहित देश में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को मार्जिन निधि सहायता प्रदान की जाती है। ओडिशा राज्य में पीएमईजीपी के तहत स्थापित की गई सूक्ष्म इकाइयों, वितरित की गई मार्जिन निधि और सृजित रोजगार का जिला-वार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *20, जिसका उत्तर दिनांक 05.02.2024 को दिया जाना है,के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-1

ओडिशा राज्य में वर्तमान वित्त वर्ष-2023-24 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण (जिलावार) (परियोजना एवं रोजगार: संख्या में, मार्जिन निधि: लाख रु में)				
क्र.सं.	राज्य/ जिला	2023-24 (30.01.2024 तक)		
		परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रु में)	रोजगार
1	अंगुल	71	286.89	568
2	बालेश्वर	133	465.34	1,064
3	बारगढ़	82	250.15	656
4	भद्रक	86	260.08	688
5	बालांगीर	82	252.96	656
6	बौध	10	23.59	80
7	कटक	165	513.99	1320
8	देवगढ़	29	67.05	232
9	ढेंकनाल	73	279.43	584
10	गजपति	18	45.28	144
11	गंजम	170	681.72	1360
12	जगतसिंहपुर	54	151.85	432
13	जाजपुर	80	211.80	640
14	झारसुगुडा	37	93.45	296
15	कालाहांडी	51	147.79	408
16	कंधमाल	16	31.58	128
17	केंद्रपाड़ा	101	297.29	808
18	क्योंझर	54	158.62	432
19	खुर्दा	203	688.77	1624
20	कोरापुट	30	97.48	240
21	मल्कानगिरी	24	51.04	192
22	मयूरभंज	134	416.34	1072
23	नबरंगपुर	26	45.47	208
24	नयागढ़	75	220.40	600
25	नुआपाड़ा	15	46.00	120
26	पुरी	176	554.92	1408
27	रायगढ़	49	154.46	392
28	संबलपुर	31	95.15	248
29	सोनेपुर	54	174.36	432
30	सुंदरगढ़	59	172.73	472
	कुल	2,188	6,935.98	17,504

स्रोत: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

श्री सुजीत कुमार: सर, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ट्राइफेड के साथ collaboration में Tech for Tribal नामक एक बहुत ही सुन्दर इनिशिएटिव शुरू किया था। इस इनिशिएटिव को tribal entrepreneurs के आईटी स्किल, बिज़नेस स्किल और सॉफ्टवेयर स्किल को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस इनिशिएटिव की क्या प्रोग्रेस हुई है, इससे कितने tribal entrepreneurs लाभ उठा चुके हैं और इसको आगे कितने सालों तक चलाया जाएगा?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष रूप से एसटीज़ के संबंध में बात की है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जितनी भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, वे पूरे देश के लिए चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से, पीएमईजीपी योजना के माध्यम से हम लोग छोटे-छोटे लोगों की मदद करते हैं। अगर इस योजना को देखा जाए तो पता चलेगा कि हमने इसके माध्यम से पूरे देश में गरीबों को जो सब्सिडी दी है, वह 2.4 हजार करोड़ रुपये है। इसमें करीब 65,000 योजनाएँ हैं, जिनमें हमने मदद की है। उसी तरीके से 5,52,000 लोगों को रोज़गार दिया गया है।

सर, विशेष रूप से जो पीएमईजीपी योजना है, इसमें ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए सब्सिडी का अलग-अलग प्रावधान किया गया है। अगर कोई शहरी एरिया है, जहाँ जनरल लोग हैं, तो उनको 15 परसेंट की सब्सिडी दी जाती है और यदि वे ग्रामीण एरियाज़ में हैं तो उन्हें 25 परसेंट की सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई एससी-एसटी शहर में रहता है तो उसे 25 परसेंट की सब्सिडी दी जाती है और यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसे 35 परसेंट की सब्सिडी दी जाती है। इस तरह से पूरे देश में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने विशेष रूप से जो पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमने ओडिशा को करीब 69 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। हम लोगों ने करीब 2,188 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है और इससे करीब 17,504 लोगों को रोज़गार मिला है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Sujeet Kumar.

श्री सुजीत कुमार: सर, मैंने Tech for Tribals scheme के बारे में सवाल पूछा था। PMEGP के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन मैं उनसे बाद में इसका उत्तर ले लूंगा।

सर, वर्ष 2022 में Standing Committee on Finance की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि जो MSMEs हैं, उनका क्रेडिट गैप 20 से 25 लाख करोड़ रुपये है। यह जनरल MSMEs के लिए है, tribal-led MSMEs or tribal-led entrepreneurs का क्रेडिट गैप close to 90 per cent है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो tribal entrepreneurs हैं, उनको credit facilities avail करने के लिए क्या-क्या स्कीम्स हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: सभापति महोदय, विशेष रूप से ट्राइबल्स की मदद के लिए पूरे देश में MSMEs की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से हम देखें तो आज हम लोग देश भर में टेक्निकल सेंटर्स बना रहे हैं, करीब 53 टेक्निकल सेंटर्स हैं और 20 नए बना रहे हैं। वे 125 करोड़ रुपये की लागत से देश भर में बनाए जा रहे हैं। उसी तरह से हम 100 एक्सटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं, जो करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 6 हजार करोड़

रुपये का बजट रखा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधान मंत्री जी ने 17 सितम्बर को विश्वकर्मा योजना लागू की है, वह उन गरीबों के लिए है, जो छोटे-छोटे लोग हैं, जो घर बैठे 18 प्रकार के ट्रेड में काम करते हैं। उनके लिए करीब 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसमें करीब 88 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आगे भी तेजी के साथ रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं - PMEGP योजना, स्फूर्ति योजना, एससी/एसटी हब आदि गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Dr. Santanu Sen.

DR. SANTANU SEN: Mr. Chairman, Sir, through you, my supplementary question on MSMEs to the hon. Minister is this: As per national records, West Bengal ranks second in MSMEs, where we have got nearly 90 lakh MSMEs and we have created nearly 136 lakh jobs through them. Now, instead of getting proper cooperation, why are non-BJP States being shown a step-motherly attitude?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये योजनाएं पूरे देश में चलाई जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो और जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। इन्होंने पश्चिमी बंगाल की बात की है, वहां लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में पश्चिमी बंगाल में PMEGP के अंतर्गत भी लोगों को लाभ मिल रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नारायण राणे): माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न ओडिशा से संबंधित है। माननीय सदस्य ने ओडिशा के बारे में MSMEs से संबंधित अलग-अलग स्कीम्स की डिटेल्स मांगी है। पश्चिमी बंगाल के लिए वे अलग से प्रश्न पूछेंगे, तो हम डिटेल्स में उत्तर देंगे।

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, given the initial challenges faced by MSMEs in setting up digital assets and ensuring cyber security, it is essential for them to enhance understanding and integration of cyber security measures. MSMEs are facing capital constraints. They are struggling with shaky technology base hindering growth and recognition. In addressing these issues, what measures does the Ministry propose to

make MSMEs more reliant on technology, overcome growth bottlenecks and add to the economy in full potential?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.